भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3149
दिनांक 06 अगस्त, 2026

ई-20 पेट्रोल की कीमत

†3149. **एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मक्का आधारित एथेनॉल के अधिसूचित क्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए बीस प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई-20) की प्रति लीटर औसत उत्पादन लागत तथा बिना मिश्रित पेट्रोल की प्रति लीटर औसत उत्पादन लागत क्या है;

(ख) उत्पादन लागत में अंतर तथा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद ई-20 पेट्रोल का मूल्य पारंपरिक पेट्रोल के समान निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में एथेनॉल मिश्रित ईंधन की बिक्री से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ मार्जिन अथवा वहन किए गए वित्तीय परिव्यय क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) ईबीपी कार्यक्रम के तहत देश भर की डिस्टिलरी से इथेनॉल की अधिप्राप्ति करती हैं। अधिप्राप्ति ढांचे को पर्याप्त इथेनॉल उपलब्धता सुनिश्चित करने, उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए, इथेनॉल की औसत अधिप्राप्ति लागत 71.55 रुपए प्रति लीटर (परिवहन और जीएसटी सहित) है।

ओएमसीज ईबीपी कार्यक्रम के तहत लाभकारी मूल्यों पर इथेनॉल खरीदती है जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। उदाहरण के लिए, मक्का आधारित इथेनॉल के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और इसका वर्तमान अधिप्राप्ति मूल्य 71.86 रुपए प्रति लीटर (परिवहन और जीएसटी को छोड़कर) है।

पश्चिम एशिया संकट के चरम के दौरान जब भारतीय क्रूड बास्केट लगभग 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तो पेट्रोल का बाजार मूल्य लगभग 125 रुपए प्रति लीटर हो सकता था, हालांकि भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा केवल 94.77 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली में) का भुगतान करना जारी रहा, क्योंकि ओएमसीज 70 रुपए प्रति लीटर की दर से इथेनॉल अधिप्राप्ति कर सकती थीं। आयातित पेट्रोल के एक हिस्से को घरेलू रूप से उत्पादित इथेनॉल से बदलकर, भारत ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य में अस्थिरता

और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए अपने जोखिम को कम कर दिया है। मार्च-जून 2026 के दौरान पेट्रोल का औसत डिपो मूल्य लगभग 85.8 रुपए प्रति लीटर था। चूंकि खुदरा बिक्री मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे रहा, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने इस अवधि के दौरान पेट्रोल पर लगभग 11 रुपए प्रति लीटर की औसत अल्प-वसूलि की, जो लगभग 21,300 करोड़ रुपए थी।

ई20 पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों, विनिमय दरों, माल ढुलाई, करों, इथेनॉल अधिप्राप्ति लागत और अन्य प्रचालन खर्चों पर विचार करने के बाद पेट्रोल के मूल्यों को निर्धारित करती हैं। तेल कंपनियों को दिनांक 01.04.2026 से देश भर में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर(आरओएन) 95 है। इथेनॉल की उच्च-ऑक्टेन संख्या आधुनिक उच्च-संपीड़न इंजनों का समर्थन करती है और इसकी वाष्पीकरण की उच्च गर्मी दहन दक्षता में सुधार करती है।

(ग): सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन गतिविधि-वार न होकर पेट्रोलियम मूल्य श्रृंखला में समेकित आधार पर किया जाता है। पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की अधिप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी अतिरिक्त लाभ या लागत को ओएमसीज द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जाता है या वहन नहीं किया जाता है। तद्नुसार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम या बिक्री किए गए इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रत्येक लीटर के लिए कोई अलग लाभ या हानि नहीं रखी जाती है या गणना नहीं की जाती है।

तद्नुसार,ईबीपी कार्यक्रम की सफलता को ओएमसीज द्वारा अर्जित लाभ के संदर्भ में नहीं मापा जाना चाहिए। इसका वास्तविक लाभांश भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करने, आयात निर्भरता को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार और दीर्घकालिक ईंधन मूल्य स्थिरता में योगदान देने में निहित है।

*****